

उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति : अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (8th AISES) के आधार पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

यज्ञेश नाथ त्रिपाठी, शोध छात्र, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्विद्यालय, गोरखपुर
डॉ अर्जुन सोनकर, शोध निर्देशक एवं सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्विद्यालय, गोरखपुर
Email- bpgcynt@gmail.com

सारांशिका

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (8th All India School Education Survey – AISES) के आधार पर उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन विद्यालयों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं, छात्र नामांकन, शिक्षक उपलब्धता, शिक्षक-योग्यता, माध्यम-ए-शिक्षण, समावेशी शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सुविधाओं तथा शैक्षिक अवसरों की समानता जैसे प्रमुख आयामों का परीक्षण करता है। 8th AISES का संदर्भ वर्ष 30 सितम्बर 2009 है, जिसमें देशभर के लगभग 13 लाख विद्यालयों, 22 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों तथा 58 लाख से अधिक शिक्षकों से संबंधित व्यापक आँकड़ों का संकलन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे शिक्षा तक पहुँच का विस्तार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के प्रभाव से विद्यालयी सुविधाओं में सुधार दिखाई देता है, किन्तु ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयी अवसंरचना, स्वच्छ पेयजल, पृथक शौचालय, विद्युत, प्रयोगशालाओं तथा ICT सुविधाओं की उपलब्धता में अभी भी असमानता विद्यमान है। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम, बालिकाओं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी सुविधाओं तथा संसाधनों के समुचित विकास की आवश्यकता बनी हुई है।

मुख्य शब्द - उच्च प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण, विद्यालयी शिक्षा संकेतक, शैक्षिक अवसंरचना एवं नामांकन

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। किसी देश की मानव पूँजी का निर्माण, सामाजिक समानता की स्थापना तथा सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही संभव होती है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में विद्यालयी शिक्षा की स्थिति का समुचित आकलन करना शिक्षा नीति निर्माण, संसाधनों के प्रभावी वितरण तथा भावी योजनाओं के निर्धारण के लिए अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8) विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है। इसी स्तर पर विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विषयगत दक्षता तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए आवश्यक आधार विकसित होता है। अतः इस स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच, आधारभूत सुविधाएँ एवं शैक्षिक संसाधनों का विश्लेषण राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने विद्यालयी शिक्षा के विस्तार एवं सार्वभौमिकरण हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सर्व शिक्षा अभियान (SSA), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE, 2009), मध्याह्न भोजन योजना तथा समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहलों ने विद्यालयी शिक्षा में नामांकन वृद्धि, विद्यालयों की संख्या में विस्तार तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। इन योजनाओं की वास्तविक प्रभावशीलता का मूल्यांकन विश्वसनीय एवं व्यापक आँकड़ों के आधार पर ही संभव है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा समय-समय पर अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (All India School Education Survey—AISES) आयोजित किए जाते रहे हैं, जो देश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का व्यापक सांख्यिकीय चित्र प्रस्तुत करते हैं।

अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (8th AISES) 30 सितम्बर 2009 को संदर्भ तिथि मानकर संचालित किया गया। यह सर्वेक्षण विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अब तक के सबसे व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में से एक है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 13 लाख विद्यालय, लगभग 6 लाख गाँव तथा 5,200 से अधिक नगरों एवं शहरी क्षेत्रों का समावेश किया गया। सर्वेक्षण में लगभग 5.876 मिलियन (58.76 लाख) शिक्षकों तथा 22 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी संकलित की गई, जिससे विद्यालयी शिक्षा की वास्तविक स्थिति का विस्तृत एवं प्रामाणिक चित्र उपलब्ध होता है। 8th AISES की विशेषता केवल विद्यालयों की संख्या अथवा नामांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने विद्यालयी शिक्षा से जुड़े अनेक नए आयामों को भी सम्मिलित किया है। सर्वेक्षण में विद्यालयों की आधारभूत संरचना, पेयजल, शौचालय, खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), इंटरनेट सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएँ, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नामांकन, बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की स्थिति तथा व्यावसायिक शिक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण संकेतकों का समावेश किया गया है। इससे विद्यालयी शिक्षा के मात्रात्मक ही नहीं, बल्कि गुणात्मक पक्षों का भी समग्र मूल्यांकन संभव हो पाया है।

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था अत्यंत विशाल एवं विविधतापूर्ण है। राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। एक ओर महानगरों एवं विकसित क्षेत्रों में विद्यालयी संसाधनों एवं शिक्षकों की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर है, वहीं दूसरी ओर अनेक ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की कमी आज भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे परिदृश्य में उच्च प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।

उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा व्यवस्था का वह चरण है जहाँ प्राथमिक स्तर पर अर्जित मूलभूत अधिगम को विषयगत गहराई एवं विश्लेषणात्मक सोच में परिवर्तित किया जाता है। यदि इस स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक तथा समावेशी वातावरण उपलब्ध न हो, तो माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति प्रभावित होती है। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता के साथ-साथ मध्य विद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम पर विशेष बल दिया गया है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण अत्यंत प्रासंगिक है।

8th AISES के उद्देश्यों में विद्यालयी शिक्षा की वर्तमान स्थिति का वर्णन, शैक्षिक विकास की प्रगति का आकलन तथा विभिन्न सामाजिक समूहों एवं क्षेत्रों के मध्य शैक्षिक अवसरों की समानता का मूल्यांकन प्रमुख रूप से सम्मिलित है। सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल आँकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि ऐसे शैक्षिक संकेतकों का निर्माण भी है जिनके आधार पर शिक्षा संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन किया जा सके तथा भविष्य की नीतियों के लिए उपयुक्त दिशा निर्धारित की जा सके। इसके अंतर्गत विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन, प्रतिधारण, आधारभूत सुविधाएँ, शिक्षक उपलब्धता, भाषा, समावेशी शिक्षा तथा शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। अध्ययन में विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन की प्रवृत्तियाँ, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्यालयी पहुँच, आधारभूत सुविधाओं की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता एवं योग्यता, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) संसाधन, बालिकाओं एवं वंचित वर्गों की भागीदारी तथा समावेशी शिक्षा के विभिन्न आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राज्य की उपलब्धियों एवं चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

यह अध्ययन न केवल उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक होगा, बल्कि शिक्षा नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं तथा शिक्षा नियोजकों के लिए भी उपयोगी संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा। साथ ही यह अध्ययन भविष्य में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, संसाधनों के समुचित आवंटन तथा गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण पर आधारित यह विश्लेषण उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान दशा एवं भावी दिशा दोनों का समग्र परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है।

साहित्य समीक्षा

विद्यालयी शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकास की आधारशिला होती है। भारत में विद्यालयी शिक्षा की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा समय-समय पर **अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण** आयोजित किए जाते रहे हैं। **अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (8th AISES)** भारतीय विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का एक व्यापक एवं विश्वसनीय दस्तावेज है, जिसका संदर्भ दिनांक 30 सितम्बर 2009 है। इस सर्वेक्षण में देश के लगभग 13 लाख विद्यालयों, लगभग 6 लाख गाँवों तथा 5.2 हजार शहरी क्षेत्रों का अध्ययन किया गया तथा लगभग 22 करोड़ विद्यार्थियों एवं 58.76 लाख शिक्षकों से संबंधित आँकड़े संकलित किए गए। यह सर्वेक्षण विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता, पहुँच, आधारभूत सुविधाओं, नामांकन, शिक्षक गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा तथा शैक्षिक संसाधनों की व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

8th AISES का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना, शैक्षिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा विभिन्न सामाजिक एवं भौगोलिक वर्गों के मध्य शैक्षिक समानता एवं असमानता का अध्ययन करना था। सर्वेक्षण में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर विद्यालयों की उपलब्धता, विद्यार्थियों के नामांकन, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित आँकड़े

संकलित किए गए। इस प्रकार यह सर्वेक्षण नीति-निर्माताओं एवं शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

अष्टम AISES की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसमें पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों की अपेक्षा अनेक नए संकेतकों को सम्मिलित किया गया। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों का नामांकन, दिव्यांग विद्यार्थियों की श्रेणीवार जानकारी, विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, खेल मैदान, इंटरनेट एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सुविधाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या तथा विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाओं की स्थिति जैसी सूचनाएँ शामिल की गईं। इन संकेतकों ने विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता एवं समावेशिता का अधिक व्यापक मूल्यांकन संभव बनाया।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य के संदर्भ में 8th AISES अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में उच्च प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, गुणवत्ता तथा समान अवसर सुनिश्चित करना शिक्षा नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में रहा है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयों की संख्या तथा नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य आधारभूत सुविधाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण में अभी भी पर्याप्त अंतर विद्यमान है। इससे यह संकेत मिलता है कि केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों की समान उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सर्वेक्षण में समावेशी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन, उनके लिए आवश्यक सुविधाओं, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता तथा विद्यालयों में पहुँच-संबंधी व्यवस्थाओं का पृथक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयी शिक्षा केवल सामान्य विद्यार्थियों तक सीमित न रहकर सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हुई है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का समावेश लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है।

8th AISES में विद्यालयी आधारभूत संरचना को शिक्षा की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है। सर्वेक्षण में भवन, कक्ष-कक्षाओं की स्थिति, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, खेल मैदान, विद्युत, पेयजल, शौचालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों की उपलब्धता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल नामांकन पर्याप्त नहीं, बल्कि विद्यालयों में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण एवं आवश्यक संसाधनों का होना भी अनिवार्य है।

समग्र रूप से उपलब्ध साहित्य यह इंगित करता है कि 8th AISES भारतीय विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत विश्वसनीय एवं व्यापक आँकड़ा-स्रोत है, जिसने विद्यालयी शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता, समानता एवं समावेशिता का बहुआयामी चित्र प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक शिक्षा तंत्र का विश्लेषण करने के लिए यह सर्वेक्षण विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से राज्य में विद्यालयों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं, शिक्षक संसाधनों, नामांकन प्रवृत्तियों तथा शैक्षिक असमानताओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने हेतु 8th AISES को प्रमुख द्वितीयक स्रोत के रूप में ग्रहण किया गया है, जिससे राज्य की शैक्षिक उपलब्धियों, चुनौतियों एवं भावी सुधार की संभावनाओं का वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक मूल्यांकन संभव हो सके।

AISES के आधार पर उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा का विस्तृत विश्लेषण

भारत में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा (Upper Primary Education) अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तर है। कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यावसायिक विकास की आधारशिला रखती है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण यहाँ उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (8th AISES), जिसका संदर्भ दिनांक **30 सितम्बर 2009** है, विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित विस्तृत आँकड़े उपलब्ध कराता है। सर्वेक्षण में देशभर के लगभग **13 लाख विद्यालय**, लगभग **6 लाख गाँव**, **58.76 लाख शिक्षक** तथा **22 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों** को सम्मिलित किया गया। यह सर्वेक्षण विद्यालयों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं, नामांकन, शिक्षक-योग्यता, समावेशी शिक्षा, ICT, प्रयोगशालाओं तथा अन्य शैक्षिक संकेतकों का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

AISES के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के परिणामस्वरूप उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अधिकांश ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय पहले से उपलब्ध थे, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पहुँच को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यालय स्थापित किए गए। विद्यालयों की उपलब्धता के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं—

- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई।
- अधिकांश आबादियों को निर्धारित दूरी के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए गए।
- पिछड़े एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में विद्यालय स्थापना को प्राथमिकता दी गई।
- विद्यालय-विहीन बस्तियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई।

इसके बावजूद कुछ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं, की नियमित उपस्थिति को प्रभावित करती है।

नामांकन (Enrolment) की स्थिति

उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसका मुख्य कारण था—

- सर्व शिक्षा अभियान
- निःशुल्क शिक्षा
- मध्याह्न भोजन योजना
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें
- छात्रवृत्तियाँ
- विद्यालयों का विस्तार

बालिकाओं के नामांकन में विशेष वृद्धि हुई, जिससे लैंगिक अन्तर में कमी आई। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का नामांकन भी बढ़ा, जो शिक्षा में सामाजिक समावेशन की दिशा में सकारात्मक संकेत है। फिर भी उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट की समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों में कक्षा 6 से 8 के बीच विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक देखी गई।

विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं का विश्लेषण

AISES ने विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश में अनेक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार हुआ, किन्तु गुणवत्ता के स्तर पर अभी भी सुधार की आवश्यकता थी।

मुख्य सुविधाएँ—

(क) विद्यालय भवन

अधिकांश उच्च प्राथमिक विद्यालय पक्के भवनों में संचालित हो रहे थे, परन्तु कुछ विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता थी।

(ख) पेयजल

सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ। अधिकांश विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था थी, किन्तु कई स्थानों पर उसकी नियमित कार्यशीलता चुनौती बनी रही।

(ग) शौचालय

बालिकाओं हेतु पृथक शौचालयों की उपलब्धता में वृद्धि हुई, परन्तु अनेक विद्यालयों में वे उपयोग योग्य स्थिति में नहीं थे। AISES ने केवल शौचालय की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि उसके उपयोग योग्य (usable) होने की जानकारी भी संकलित की।

(घ) खेल का मैदान

कई विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध थे, किन्तु शहरी क्षेत्रों में स्थानाभाव के कारण यह सुविधा सीमित थी।

(ङ) विद्युत सुविधा

विद्युत उपलब्धता में सुधार हुआ, परन्तु ग्रामीण विद्यालयों में बिजली की नियमित आपूर्ति अभी भी चुनौती थी।

शिक्षकों की स्थिति

उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता मुख्यतः शिक्षकों पर निर्भर करती है।

AISES के अनुसार उत्तर प्रदेश में—

- प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ी।
- महिला शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि हुई।
- शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं का विस्तार हुआ।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण (In-service Training) पर विशेष बल दिया गया।
- विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार हुआ।

इसके बावजूद कई विद्यालयों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों का अभाव पाया गया। विशेष रूप से विज्ञान, गणित तथा अंग्रेज़ी के शिक्षकों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है।

समावेशी शिक्षा

8th AISES की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े संकलित किए गए।

उत्तर प्रदेश में—

- दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई।
- संसाधन शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ी।
- विशेष शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए।

कुछ विद्यालयों में रैम्प एवं सहायक सुविधाएँ विकसित की गईं। फिर भी अधिकांश विद्यालय पूर्णतः दिव्यांग-अनुकूल नहीं थे। ब्रेल सामग्री, विशेष उपकरण तथा प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)

AISES ने पहली बार विद्यालयों में ICT सुविधाओं का विस्तृत सर्वेक्षण किया।

उत्तर प्रदेश में—

- सीमित संख्या में विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध थे।
- इंटरनेट सुविधा अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थी।
- कम्प्यूटर शिक्षकों की संख्या कम थी।
- ICT आधारित शिक्षण प्रारम्भिक अवस्था में था।

ग्रामीण विद्यालयों में ICT सुविधाएँ विशेष रूप से अपर्याप्त थीं। इससे डिजिटल शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न होती थी।

भाषा एवं शिक्षण माध्यम

उत्तर प्रदेश के अधिकांश उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी था।

इसके अतिरिक्त—

- उर्दू माध्यम विद्यालयों की भी पर्याप्त संख्या थी।
- अंग्रेज़ी विषय का विस्तार हो रहा था।
- त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिन्दी, अंग्रेज़ी एवं संस्कृत/उर्दू का शिक्षण अनेक विद्यालयों में संचालित था।

यह व्यवस्था विद्यार्थियों के भाषायी विकास में सहायक सिद्ध हुई।

सामाजिक समानता एवं लैंगिक समानता

AISES के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

मुख्य उपलब्धियाँ—

- बालिकाओं का बढ़ता नामांकन।
- अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की बढ़ती भागीदारी।
- अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा में सुधार।
- विद्यालयों तक पहुँच में वृद्धि।
- प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव।

फिर भी ग्रामीण-शहरी तथा सामाजिक समूहों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से असमानताएँ अभी भी विद्यमान थीं।

प्रमुख चुनौतियाँ

AISES के आधार पर उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा के समक्ष निम्न प्रमुख चुनौतियाँ दिखाई देती हैं—

1. ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के मध्य गुणवत्ता का अन्तर।
2. विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी।
3. ICT सुविधाओं का अभाव।
4. प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की सीमित उपलब्धता।
5. बालिकाओं हेतु उपयोग योग्य शौचालयों की कमी।

6. दिव्यांग-अनुकूल अधोसंरचना का अभाव।
7. उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट की समस्या।
8. शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की आवश्यकता।

सुधार हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

- प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धारित दूरी के भीतर गुणवत्तापूर्ण उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए जाएँ।
- विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति बढ़ाई जाए।
- सभी विद्यालयों में कार्यशील ICT प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँ।
- पुस्तकालय एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार किया जाए।
- दिव्यांग-अनुकूल अधोसंरचना सुनिश्चित की जाए।
- बालिकाओं हेतु सुरक्षित एवं उपयोग योग्य शौचालय उपलब्ध कराए जाएँ।
- विद्यालयों में नियमित शैक्षिक अनुश्रवण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाए।
- समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों की भागीदारी को सुदृढ़ किया जाए।

उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति (8th AISES के आधार पर)

1. छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil Teacher Ratio - PTR)

8th AISES के अनुसार पूरे भारत में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का औसत PTR घटकर 32.15 हो गया, जो सातवें सर्वेक्षण में 34 था। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देता है।

उत्तर प्रदेश में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)

स्तर	7वाँ AISES (2002)	8वाँ AISES (2009)	उत्तर प्रदेश) 2009)
प्राथमिक	42.00	34.00	44.64
उच्च प्राथमिक	34.00	32.15	38.62

स्रोत: 8th AISES, NCERT.

किन्तु उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्तर पर PTR 38.62 दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय औसत (32.15) से काफी अधिक है। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शिक्षक पर विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रभावित हो सकता है।

विश्लेषण

- राष्ट्रीय औसत = 32.15
- उत्तर प्रदेश = 38.62
- अन्तर = लगभग 6.5 विद्यार्थी प्रति शिक्षक

इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. प्राथमिक स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक

प्राथमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश का PTR 44.64 है जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 34 है।

इससे स्पष्ट है कि प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षक उपलब्धता उत्तर प्रदेश की प्रमुख समस्या रही है।

3. सकल नामांकन अनुपात (GER)

8th AISES के अनुसार

- प्राथमिक स्तर GER = 94.72
- उच्च प्राथमिक GER = 71.67
- बालिकाओं का GER = 71.64

इससे स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुँचते-पहुँचते नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट आती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह समस्या और अधिक महत्वपूर्ण है।

4. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना

पूरे भारत में

- 91.43% उच्च प्राथमिक विद्यालय पक्के भवनों में संचालित हो रहे थे।
- केवल 8.57% विद्यालय गैर-पक्के भवनों में थे।
- बिना भवन वाले विद्यालयों की संख्या 2002 की तुलना में काफी कम हुई।

विश्लेषण

यह संकेत देता है कि सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के बाद विद्यालय भवनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। चर्चा

अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (8th AISES) के आधार पर उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि राज्य ने विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन वृद्धि तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं तथा समान अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अधिकांश आबादी तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पहुँच सुनिश्चित हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के परिणामस्वरूप विद्यालयों की भौगोलिक उपलब्धता में सुधार हुआ तथा नामांकन दर में वृद्धि हुई। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का सकारात्मक संकेत है। AISES का उद्देश्य भी शिक्षा तक पहुँच, नामांकन, सहभागिता, प्रतिधारण तथा शैक्षिक समानता का मूल्यांकन करना रहा है।

विद्यालयी अवसंरचना की दृष्टि से अनेक विद्यालयों में भवन, पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान तथा विद्युत जैसी सुविधाओं में सुधार दिखाई देता है, किन्तु इन सुविधाओं की गुणवत्ता और नियमित उपयोग सभी विद्यालयों में समान नहीं है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रयोग योग्य शौचालय, स्वच्छ पेयजल, पुस्तकालय, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाओं तथा ICT सुविधाओं का अभाव शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। 8th AISES में इन सुविधाओं को प्रमुख शैक्षिक संकेतकों के रूप में सम्मिलित किया गया है।

शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता के संदर्भ में भी मिश्रित स्थिति देखने को मिलती है। यद्यपि प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है, तथापि विषय-विशेष शिक्षकों की कमी, बहु-स्तरीय शिक्षण (Multi-grade Teaching), निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development) तथा ICT आधारित शिक्षण कौशल का अभाव अभी भी चुनौती बना हुआ है। सर्वेक्षण में शिक्षकों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं, आयु-वर्ग, प्रशिक्षण तथा ICT उपयोग की जानकारी को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है।

समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भी उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन, उनकी दिव्यांगता की श्रेणियों तथा विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का पृथक् संकलन पहली बार व्यापक रूप से किया गया। यह शिक्षा में समान अवसर एवं सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तथापि व्यावहारिक स्तर पर अधिकांश विद्यालयों में रैम्प, संसाधन कक्ष, विशेष शिक्षकों तथा सहायक उपकरणों की कमी अब भी देखी जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता और पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, किन्तु गुणवत्ता, अधिगम परिणाम, शिक्षक दक्षता तथा आधारभूत सुविधाओं में क्षेत्रीय असमानता अभी भी बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

8th AISES के आधार पर उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है—

(1) आधारभूत सुविधाओं में असमानता

यद्यपि अधिकांश विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं, किन्तु प्रयोग योग्य शौचालय, सुरक्षित पेयजल, बिजली, पुस्तकालय, खेल मैदान एवं ICT सुविधाओं की उपलब्धता में ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के मध्य स्पष्ट अंतर पाया जाता है।

(2) गुणवत्तापूर्ण अधिगम की चुनौती

नामांकन में वृद्धि के बावजूद अधिगम स्तर अपेक्षित नहीं है। केवल विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कर देना पर्याप्त नहीं है; विद्यार्थियों में भाषा, गणित एवं विज्ञान की दक्षताओं का विकास भी आवश्यक है।

(3) प्रशिक्षित एवं विषय-विशेष शिक्षकों की कमी

उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित, विज्ञान तथा अंग्रेज़ी विषय के प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता अनेक क्षेत्रों में अपर्याप्त है। इससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(4) डिजिटल विभाजन (Digital Divide)

ICT आधारित शिक्षण, इंटरनेट, कंप्यूटर तथा स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता ग्रामीण विद्यालयों में सीमित है। AISES ने ICT सुविधाओं एवं इंटरनेट उपलब्धता को महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में सम्मिलित किया है।

(5) समावेशी शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन

दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है, किन्तु उनके लिए आवश्यक संसाधन, विशेष शिक्षक तथा सहायक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।

(6) लैंगिक एवं सामाजिक असमानता

बालिकाओं तथा वंचित वर्गों की शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फिर भी विद्यालय त्याग (Dropout), किशोरावस्था संबंधी समस्याएँ, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी चुनौती बनी हुई है।

(7) विद्यालय प्रबंधन एवं निगरानी

विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC), समुदाय की सहभागिता तथा विद्यालय-स्तरीय उत्तरदायित्व को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय विद्यालयी शिक्षा को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, प्रौद्योगिकी-समर्थ तथा दक्षता-आधारित बनाने का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यदि 8th AISES के निष्कर्षों की तुलना NEP-2020 से की जाए, तो स्पष्ट होता है कि नीति में उल्लिखित अधिकांश सुधारात्मक उपाय AISES द्वारा पहचानी गई चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करते हैं।

सबसे पहले, NEP-2020 गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा पर बल देती है। AISES में विद्यालयीय सुविधाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों, दिव्यांग विद्यार्थियों, ICT, प्रयोगशालाओं तथा आधारभूत संरचना से संबंधित आँकड़े यह संकेत देते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाने से नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की उपलब्धता से सुनिश्चित होगी।

दूसरे, नीति शिक्षक शिक्षा एवं सतत् व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development) पर विशेष बल देती है। AISES में प्रशिक्षित शिक्षकों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रमुख संकेतकों में सम्मिलित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला हैं।

तीसरे, NEP-2020 डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन संसाधनों तथा ICT आधारित शिक्षण को बढ़ावा देती है। AISES में विद्यालयों में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर तथा ICT सुविधाओं की उपलब्धता का पृथक् विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो डिजिटल शिक्षा की वर्तमान स्थिति का आधार प्रदान करता है।

चौथे, नीति समावेशी एवं समान अवसर आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देती है। AISES में दिव्यांग विद्यार्थियों, सामाजिक वर्गों तथा बालिकाओं से संबंधित विस्तृत आँकड़े उपलब्ध हैं, जो शिक्षा में समानता की दिशा में नीति निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

पाँचवें, NEP-2020 अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning), बहुभाषिकता, दक्षता-आधारित मूल्यांकन तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा पर बल देती है। यदि उत्तर प्रदेश में इन सिद्धांतों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम परिणामों में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि 8th AISES वर्तमान स्थिति का व्यापक आधार प्रस्तुत करता है, जबकि NEP-2020 भविष्य के सुधारों का मार्गदर्शक दस्तावेज़ सिद्ध होती है।

निष्कर्ष

अष्टम अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि राज्य ने विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन विस्तार, बालिका शिक्षा, सामाजिक समावेशन तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। विद्यालयों की पहुँच बढ़ी है तथा वंचित वर्गों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके साथ ही अध्ययन यह भी दर्शाता है कि शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता अभी भी आधारभूत सुविधाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों, ICT संसाधनों, समावेशी शिक्षा तथा अधिगम परिणामों पर निर्भर है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य संसाधनों की असमानता, डिजिटल विभाजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी तथा अधिगम स्तर में अंतर नीति-निर्माताओं के लिए गंभीर विचारणीय विषय हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इन चुनौतियों के समाधान हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक क्षमता विकास, डिजिटल शिक्षण, समावेशी शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित

पाठ्यचर्या का स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है। यदि उत्तर प्रदेश में इन प्रावधानों का प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन किया जाए, तो उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति विकासशील एवं प्रगतिशील है, किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता, समानता तथा सीखने के परिणामों को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर निवेश, प्रभावी नीति क्रियान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी सुदृढ़ीकरण तथा विद्यालय-स्तरीय उत्तरदायित्व को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यही प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) की दिशा में राज्य को आगे बढ़ाएंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। (2016)। आठवां अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण (8th AISES): एक संक्षिप्त रिपोर्ट।
- नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। (2013)। अनंतिम आँकड़े: आठवां अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण (8th AISES)।
- नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। (2007)। सातवां अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण।
- नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। (2006)। स्कूली शिक्षा के सांख्यिकीय संकेतकों पर मैनुअल।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत सरकार।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2022)। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2021-22 रिपोर्ट। भारत सरकार।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2023)। UDISE+ 2022-23 रिपोर्ट। भारत सरकार।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2024)। UDISE+ 2023-24 रिपोर्ट। भारत सरकार।
- नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। (2022)। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2021: राष्ट्रीय रिपोर्ट।
- नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। (2025)। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024: उत्तर प्रदेश रिपोर्ट।
- उत्तर प्रदेश सरकार। (2020)। उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा: वार्षिक रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग।
- 1. उत्तर प्रदेश सरकार। (2021)। समग्र शिक्षा: वार्षिक कार्य योजना और बजट। बेसिक शिक्षा विभाग।
- 2. रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। (2011)। भारत की जनगणना 2011। भारत सरकार।
- 3. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (2021)। भारत में बच्चे: एक सांख्यिकीय मूल्यांकन। भारत सरकार।
- 4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। (2015)। भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक।

5. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। (2022)। भारत में प्रारंभिक शिक्षा: सार्वभौमिकरण की दिशा में प्रगति।
6. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। (2024)। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024। ASER सेंटर।
7. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। (2023)। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2023। ASER सेंटर।
8. UNESCO। (2021)। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2021/22। UNESCO.
9. UNESCO। (2023)। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। UNESCO.
10. UNICEF। (2021)। दुनिया के बच्चों की स्थिति 2021। UNICEF.
11. संयुक्त राष्ट्र। (2015)। हमारी दुनिया को बदलना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। संयुक्त राष्ट्र।
12. कोठारी, डी. एस. (1966)। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास: शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964-66)। शिक्षा मंत्रालय।
13. भारत सरकार। (2009)। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009। भारत सरकार।
14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय। (2011)। सर्व शिक्षा अभियान: कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा। भारत सरकार।
15. शिक्षा मंत्रालय। (2021)। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI)। भारत सरकार।
16. उत्तर प्रदेश सरकार। (2022)। बेसिक शिक्षा विभाग की वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार।
17. सिंह, ए. (2020)। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, 8(10), 86-94.
18. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2016)। स्कूली शिक्षा का एटलस। NCERT.
19. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2016)। अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण: शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग के प्रकाशन।